

**न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर**  
**अपील संख्या:- 498/2017 (18 आयुध अधिनियम 1959 )**

जगवीर सिंह पुत्र श्री नवलसिंह जाति गुर्जर निवासी मोहन नगर हिण्डौन जिला करौली  
करौली (राज0)

.....अपीलान्ट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली।

.....रैस्पॉडैन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
करौली दिनांक 13.3.2015

उपस्थिति:-

1. श्री पुष्पेन्द्रसिंह वकील अपीलान्ट।
1. सहायक लोक अभियोजक भरतपुर

**निर्णय**

दिनांक:30.01.2019

यह अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के निर्णय दिनांक 13.03.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था की दृष्टिगत रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने पत्रांक 9356-9395 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने शस्त्र दिनांक 03.01.2015 से पूर्व संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश पारित किये। जिसकी सूचना स्थानीय समाचार पत्रों से करायी गयी। पुनः दैनिक भास्कर एवं राष्ट्रदूत के स्थानीय संस्करण दिनांक 14.01.2015 के द्वारा शस्त्र जमा कराने का अन्तिम अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 12.02.2015 के अनुसार अनुज्ञापत्रधारियों ने अपने शस्त्र जमा नहीं कराकर आर्म्स एक्ट का उलंघन किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश क्रमांक न्याय/15/1650 दिनांक 13.03.2015 से 20 अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को आर्म्स एक्ट 1959 का उलंघन करने पर अग्रिम आदेश तक निलम्बित कर दिया। जिसमें अपीलान्ट का शस्त्र क्रम सं0 10 पर दर्ज है। इस आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है।

यह कि तहत अदालत ने अपीलधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाकर अपीलधीन आदेश उसकी बैक पर पारित किया गया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। वकील अपीलान्त का कथन है कि अपीलान्त का अनुज्ञापत्र काफी पुराना है एवं नियमानुसार नियमित नवीनीकरण भी होता रहा है साथ ही समय समय पर अनुज्ञापन अधिकारी के प्रत्येक आदेश की अपीलान्त द्वारा पालना की जाती रही है। आज भी अनुज्ञापन अधिकारी के आदेश की पालना में वर्तमान में अपीलान्त का शस्त्र संबंधित थाना थाने में जमा है। तहत अदालत ने अपीलधीन आदेश पारित किया गया है जो कतई न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता क्यों कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलान्त का अनुज्ञापन बिना किसी कारण के बिना अपीलान्त को सुने अपीलान्त के शस्त्र अनुज्ञापनत्र को अनिश्चित काल के लिये निलम्बित कर दिया है जो कानून के खिलाफ है। आयुध अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत शस्त्र अनुज्ञापत्र अनिश्चित काल के लिये निलम्बित नहीं किया जा सकता। अनुज्ञापत्र अधिकारी को वाजिब कारण सहित एक निश्चित अवधि तय करनी चाहिए थी किन्तु यहां तहत अदालत के पास न तो कोई कारण था और नहीं कोई वजह। बाबजूद इसके मनमाने तरीके से अपीलधीन आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं है। अपीलधीन आदेश के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यह गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया आदेश नहीं है। अपीलधीन आदेश के अंतर्गत एक ही आदेश से 20 लाईसेंसो को निलम्बित किया गया है जिससे यह साफ है कि अपीलान्त को न तो सुना गया न ही उसके व हैसियत अनुज्ञापत्रधारी के मापदण्डों का परीक्षण किया गया न ही ऐसी कोई वजह स्पष्ट हो सकी जिससे अपीलान्त के अनुज्ञापत्र को बहाल न किया जा सके। अपीलधीन आदेश अपीलान्त की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिए अपीलान्त को इसकी जानकारी ही नहीं थी। इसके अलावा वकील अपीलान्त का कथन है कि आदेश की पालना में अपीलान्त ने अपना शस्त्र दिनांक 25.5.2015 को जमा कराया जो आज भी जमा है। अपीलान्त की तबीयत ठीक नहीं रहती है उसका इलाज भी चल रहा है। तबीयत ठीक होते ही तहत अदालत के आदेश की पालना की गई है। अपीलान्त के विरुद्ध न कोई शस्त्र दुरुपयोग किया है न अवहेलना की गई है, न ही अनुज्ञापत्र की किसी शर्त का उल्लघन ही किया गया है, न कोई ऐसी ठोस वजह है बाबजूद इसके अपीलान्त को बिना सुने उसकी बैक पर अपीलधीन आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं है। इसके अलावा जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने अपने पत्र दिनांक 30.11.2016 से अनुज्ञापत्र बहाल किये जाने की अभिशंखा की थी उस पर भी तहत अदालत द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। चूंकि अपीलधीन आदेश बिना सुने अपीलान्त की बैक पर पारित किया गया है इसलिए इस आदेश की अपीलान्त को कतई जानकारी नहीं हुई। चूंकि अपीलान्त अपनी बीमारी के सिलसिले में जयपुर था। जानकारी होते ही कई बार तहत अदालत में अनुज्ञापत्र बहाली हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये अतः दिनांक 8.11.2017 को तहत अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से अनुज्ञापत्र बहाल किये जाने से इन्कार करने के उपरान्त वकील से सम्पर्क एवं दस्तावेजात इत्यादि की पूर्ति होने पर

अपीलान्ट द्वारा बिना किसी देरी के अपील श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। जिसके लिये पृथक से दफा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि तहत अदालत का निर्णय विधि सम्मत् नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने के आदेश दिये जावे।

रैस्पोंडेन्ट की ओर से उपस्थित सहायक लोक अभियोजक द्वारा तहत अदालत जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.3.2015 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह है कि कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपने आदेश क्रमांक न्याय/ पंआचु. 15/9356 दिनांक 29.12.14 से सभी अनुज्ञाधारियों को शस्त्र संबंधित थाने में जमा कराने के आदेश दिये गये थे। परन्तु अपीलान्ट ने अपना शस्त्र थाने में जमा नहीं कराया। इसके बाद जिला पुलिस अधीक्षक करौली ने पत्रांक 1583 दिनांक 12.02.15 से अपने हथियार जमा कराने की सूचना दी थी परन्तु सूचना देने के बाबजूद हथियार जमा नहीं कराने पर पुलिस अधीक्षक ने उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने की कार्यवाही करने का पत्र कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली को जारी किया। जिसके आधार पर कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2015 को पारित किया। तहत अदालत ने अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर सूचना के माध्यम से दिया है परन्तु अपीलान्ट ने उक्त सूचना पर शस्त्र जमा नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा-5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि:-

“Limitation Act, 1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by state Govt. the Court, Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large

would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants”

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि-

“Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling The appeal“

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलाधीन आदेश पंचायत आम चुनाव 2015 के दौरान कानून एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली के द्वारा पारित किया गया था जो तत्समय उचित था किन्तु अपीलान्ट का कहना है कि अखबार साया के माध्यम से शस्त्र जमा कराने बाबत आदेश की अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी चूंकि अखबार की सूचना से अपीलान्ट महरूम रह गया अन्यथा आदेश की अक्षरशः पालना की जाती। लेकिन वर्तमान में आदेश की पालना करते हुये अपीलान्ट का शस्त्र संबधित थाने में जमा है। अपीलान्ट के इस कथन से हम सहमत है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से 20 अनुज्ञापत्रधारियों के अनुज्ञापत्र निलम्बित किये हैं। वास्तव में उक्त आदेश स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं है। न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों की मंशा के मध्यनजर प्रत्येक व्यथित व्यक्ति को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये। दौराने पारित अपीलाधीन आदेश यदि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाता तो वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते थे । किन्तु कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट करौली द्वारा तत्कालीन कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुये समयाभाव होने की स्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया था। वर्तमान में चूंकि परिस्थितियां परिवर्तित हो गई है। अतः प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रकरण (केवल अनुज्ञापत्र संख्या 152/डीएम/केएलआई/2004 के संबध में अपीलाधीन आदेश की क्रम संख्या 10 की हद तक) पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये आयुध अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वर्तमान में कानून एवं शान्ति-व्यवस्था के औचित्य को दृष्टिगत रखते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः तार्किक एवं न्याय संगत व स्पीकिंग आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर मूथा)  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर